PRGI : APHIN/26/A3657

पेन पॉवर

वर्ष - 1 अंक - 2 शनिवार, जुलाई 4, 2026 हैदराबाद संपादकः गंट्यादा अप्पाराव पृष्ठों. 4 मूल्य. 1रु

आंध्र प्रदेश को स्टील स्टेट बनाएंगे : मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू

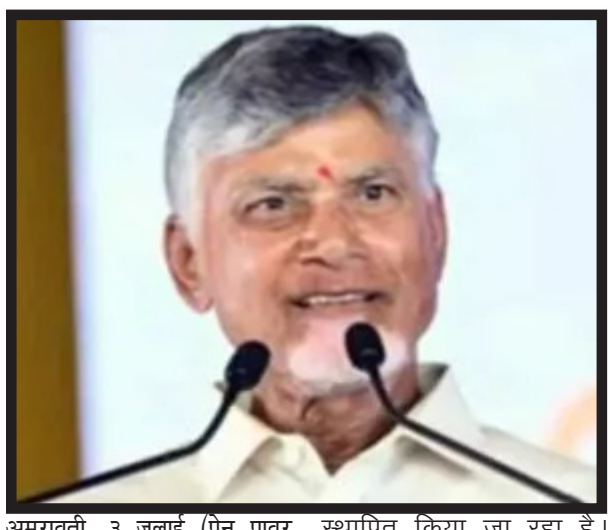

अमरावती, ३ जुलाई (पेन पावर न्यूज): आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य राज्य को एक नए औद्योगिक केंद्र, विशेष रूप से "स्टील स्टेट" के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री ने कडपा जिले के जम्मलमडुगु मंडल के सुन्नापुरल्लापल्ले गांव में 16,350 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले प्रतिष्ठित जेएसडब्ल्यू रायलसीमा स्टील प्लांट के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि राज्य में देश का पहला ग्रीन स्टील उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केवल विशाखापट्टनम ही नहीं, बल्कि पूरे रायलसीमा क्षेत्र को भी "उक्कु सीमा" (स्टील क्षेत्र) के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अतीत में कुछ लोगों ने स्टील प्लांट के नाम पर लौह अयस्क की तस्करी की थी। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार के कार्यकाल में रायलसीमा क्षेत्र में 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश लाए गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्थानीय स्तर पर उद्योग स्थापित कर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

नायडू ने कहा कि अनंतपुर जिले में किया उद्योग की स्थापना से उस क्षेत्र की तस्वीर बदल गई। उन्होंने बताया कि अब तक वहां लगभग 19 लाख वाहन निर्मित किए जा चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इतिहास को याद करें और देखें कि रायलसीमा के विकास में किसका योगदान रहा और किसके कारण क्षेत्र को नुकसान हुआ।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "एक समय रायलसीमा में फैली गुटबाजी (फैक्शन संस्कृति) को हमने समाप्त किया। रायलसीमा में खून नहीं, बल्कि सिंचाई का पानी बहना चाहिए। गुटबाजी भले कम हुई हो, लेकिन अपराध करने वाले लोगों का राजनीति में आना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसका एजेंडा केवल विनाश हो, वह राज्य के लिए क्या कर सकता है? 2014 में सभी ने सर्वसम्मति से अमरावती को राजधानी के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद कुछ लोगों ने तीन राजधानियों की बात करके राज्य को उपहास का विषय बना दिया। वे गैर–जिम्मेदाराना और असंगत बयान दे रहे हैं। यदि कोई महिलाओं या बेटियों के खिलाफ अपराध करेगा, तो वह उसका आखिरी दिन होगा। राज्य में गुंडा तत्वों और गांजा गिरोहों को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) का संरक्षण प्राप्त है। ऐसी असामाजिक शक्तियों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी।"

अगले सप्ताह न्यूजीलैंड दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी,

पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने की घोषणा

FILE PHOTO

नई दिल्ली, ३ जुलाई (एजेंसी): न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने शुक्रवार को घोषणा की कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह अपने पहले आधिकारिक न्यूजीलैंड दौरे पर जाएंगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस यात्रा की पुष्टि करते हुए लक्सन ने दौरे की सटीक तारीखों का खुलासा नहीं किया। लक्सन ने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह न्यूजीलैंड की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करेंगे।" उन्होंने इस दौरे को दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया।

भारत की बढ़ती वैश्विक आर्थिक ताकत का उल्लेख करते हुए लक्सन ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है तथा न्यूजीलैंड की आर्थिक समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण देश है। उन्होंने कहा कि अप्रैल में हस्ताक्षरित न्यूजीलैंड–भारत मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के जरिए दोनों देश अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं।

लक्सन के अनुसार, यह समझौता न्यूजीलैंड में रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि और आर्थिक विकास को गति देगा। उन्होंने कहा कि इससे न्यूजीलैंड के व्यवसायों को भारत के 1.4 अरब उपभोक्ताओं वाले विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी, जिससे स्थानीय समुदायों की आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और वेतन स्तर में सुधार होगा।भारत और न्यूजीलैंड ने इस वर्ष मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देना तथा दोनों देशों के बीच निवेश को प्रोत्साहित करना है। इस समझौते के तहत भारत के 100 प्रतिशत निर्यात को न्यूजीलैंड में शुल्क–मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत के लिए यह समझौता एक उच्च आय वाले, नियम–आधारित प्रशांत बाजार तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है और उसकी व्यापक इंडो–पैसिफिक आर्थिक रणनीति को मजबूती देता है। वहीं न्यूजीलैंड के लिए यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करता है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंध व्यापारिक आंकड़ों में भी दिखाई देते हैं। वर्ष 2024–25 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 1.3 अरब डॉलर रहा, जबकि वस्तुओं और सेवाओं सहित कुल व्यापार लगभग 2.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया। केवल सेवा क्षेत्र का व्यापार 1.24 अरब डॉलर रहा, जिसमें यात्रा, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और व्यावसायिक सेवाओं का प्रमुख योगदान रहा। यह दोनों देशों के बीच सहयोग के लगातार विस्तार को दर्शाता है।

चीराला में 6 महीने के शिशु का अपहरण, 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार

बापटला, ३ जुलाई (पेन पावर न्यूज) : चीराला में छह महीने के एक शिशु के अपहरण के मामले को पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया और इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुरुवार को वेटापालेम मंडल के कोत्तापेट ग्राम पंचायत क्षेत्र में अपनी मां के पास खुले स्थान पर सो रहे एक बालक का एक अज्ञात व्यक्ति ने कथित रूप से अपहरण कर लिया। बच्चे के लापता होने पर उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज सहित विभिन्न तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस के अनुसार, शिशु का अपहरण दासरी संजीव राव और दासरी श्रीनु ने किया था। इसके अलावा, पुलिस ने कट्टा आदिनारायण और उनकी पत्नी कट्टा तिरुमला को टंगुटूरु के पास हिरासत में लिया। जांच में पता चला कि कथित रूप से संतान न होने के कारण दंपति ने इस अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस ने बताया कि दंपति ने शिशु को लाकर देने के बदले अपहरणकर्ताओं को 1 लाख रुपये देने का प्रस्ताव दिया था। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर शिशु को अपहरणकर्ताओं के कब्जे से सुरक्षित बरामद कर उसके माता–पिता को सौंप दिया।

आंध्र प्रदेश के विकास के लिए उद्योग और निवेश आवश्यकः गृह मंत्री अनिता

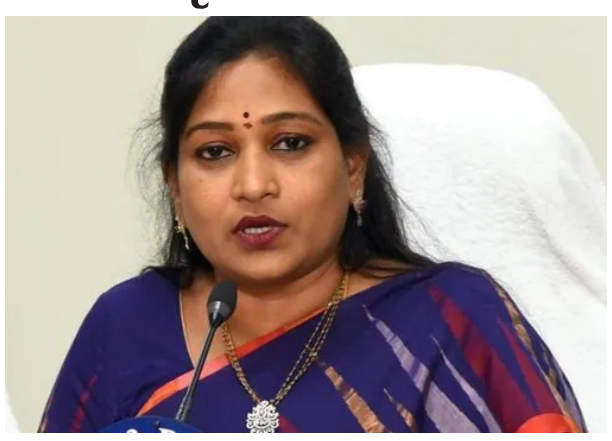

अमरावती, ३ जुलाई (पेन पावर न्यूज): आंध्र प्रदेश में औद्योगिक पार्कों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कडपा जिले के जम्मलमडुगु से वर्चुअल माध्यम से विजयनगरम जिले के शृंगवरपुकोटा मंडल में औद्योगिक पार्कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया।

इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री वंगलापुडी अनिता, मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास तथा विशाखापट्टनम सांसद एम. श्रीभारत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए अनिता ने कहा कि राज्य के विकास के लिए उद्योगों और निवेश का आना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसान और उसकी भूमि का संबंध वैसा ही होता है जैसा एक मां और उसके बच्चे का होता है। उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

मंत्री ने कहा कि पहले चरण में 535 एकड़ क्षेत्र में एक एमएसएमई पार्क स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न उद्योगों की स्थापना से लगभग 45,000 लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अनिता ने कहा कि आने वाले वर्षों में एस. कोटा विधानसभा क्षेत्र और अधिक विकसित होगा। भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने कभी सवाल उठाया था कि जहां लाल बस (सरकारी बस सेवा) भी ठीक से नहीं पहुंचती, वहां हवाई अड्डा कैसे बनेगा। लेकिन अब भोगापुरम हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए लगभग तैयार है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर आंध्र के लोग रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में पलायन करते थे, जबकि अब विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोग उत्तर आंध्र की ओर आ रहे हैं।

तंबाकू खरीद में अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी: मंत्री अच्चेन्नायडु

अमरावती, ३ जुलाई (पेन पावर न्यूज): आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री अच्चेन्नायडु ने शुक्रवार को वर्जीनिया तंबाकू की खरीद को लेकर एक टेलीकॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी नीलामी प्लेटफॉर्म तुरंत शुरू किए जाएं और प्रत्येक कंपनी के लिए नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना अनिवार्य किया जाए। मंत्री ने तंबाकू की अस्वीकृति (रिजेक्शन) दर को कम करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कंपनियां आपस में गठजोड़ (सिंडिकेट) बनाकर अच्छी गुणवत्ता वाली गांठों (बेल्स) पर भी मूल्य सीमा लगाकर कीमतें कम करने की कोशिश करती हैं, तो इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने तंबाकू बोर्ड को निर्देश दिया कि यदि किसी प्रकार की सांठगांठ या सिंडिकेट गतिविधि की पुष्टि होती है, तो संबंधित कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

अच्चेन्नायडु ने कहा कि कंपनियों को सभी ग्रेड के तंबाकू की खरीद करनी होगी और तंबाकू बोर्ड को खरीद प्रक्रिया पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे तंबाकू बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार अपना तंबाकू नीलामी केंद्रों पर लाएं। इससे उन्हें बेहतर मूल्य मिलेगा और रिजेक्शन दर भी कम होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार तंबाकू बोर्ड और बैंकों के साथ चर्चा कर उन किसानों को ऋण उपलब्ध कराएगी जो तत्काल बिक्री के बजाय तंबाकू का भंडारण करना चाहते हैं।

उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी और तंबाकू किसानों के हितों के मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब गाली–गलौज का लाइसेंस नहीं: कंदुला दुर्गेश

विजयवाड़ा (पेन पावर न्यूज): आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री कंदुला दुर्गेश ने सोशल मीडिया पर की जा रही अश्लील पोस्टों, व्यक्तिगत टिप्पणियों और भ्रामक प्रचार पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ गाली–गलौज करने का लाइसेंस नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा। मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर जानबूझकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पवन कल्याण को राजनीतिक रूप से कमजोर कर गठबंधन सरकार को नुकसान पहुंचाने की रणनीति के तहत वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) काम कर रही है। दुर्गेश ने कहा कि केवल व्यूज बढ़ाने या ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों को सवाल पूछने और आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा की सीमाएं लांघने का अधिकार नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर नियंत्रण और जवाबदेही की आवश्यकता भी बताई।

इस दौरान मंत्री ने रुशिकोंडा पैलेस मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रुशिकोंडा पैलेस का उपयोग पर्यटन विकास और आम जनता के भ्रमण के लिए किया जाएगा। इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (म्व्) आमंत्रित किया गया है। दुर्गेश ने कहा कि पिछली सरकार की नीतियों के कारण पर्यटन विभाग को हर साल लगभग 7 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और अब पर्यटन क्षेत्र के विकास तथा सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

रुशिकोंडा भवनों पर एपीटीडीसी का बड़ा फैसला, निजी कंपनियों को दी हरी झंडी

अमरावती, 3 जुलाई (पेन पावर न्यूज):आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने रुशिकोंडा भवनों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। निगम ने हिलटॉप परिसर के प्रबंधन, संचालन और विपणन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित करते हुए अधिसूचना जारी की है।

सरकार ने रुशिकोंडा परियोजना को लीज, ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस (O&M) मॉडल के तहत विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत एपीटीडीसी निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। चयनित निजी संस्था पांच भवनों वाले इस परिसर का संचालन और प्रबंधन करेगी। सरकार 9.8 एकड़ के पूरे हिलटॉप प्रोजेक्ट का उपयोग ब्–ड मॉडल के तहत करेगी। इसके अलावा रुशिकोंडा के निचले क्षेत्र में स्थित अतिरिक्त 9 एकड़ भूमि के विकास की भी अनुमति दी जाएगी। एपीटीडीसी ने बताया कि होटल, रिसॉर्ट और पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

निगम ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आम जनता के लिए सुलभ व्यूइंग एरिया और ओपन स्पेस अनिवार्य रूप से बनाए जाएं। मौजूदा भवनों के अतिरिक्त नए विकास कार्यों की भी अनुमति दी गई है। दो खाली भूखंडों पर कुल 2,400 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकास किया जा सकेगा, जबकि अतिरिक्त रूप से लगभग 4,800 वर्ग मीटर तक जी1 निर्माण की अनुमति भी दी जाएगी।

एपीटीडीसी ने स्पष्ट किया कि सभी निर्माण कार्य तटीय विनियमन क्षेत्र नियमों और अन्य वैधानिक स्वीकृतियों के अनुरूप ही किए जाएंगे। म्व् प्रक्रिया के माध्यम से निवेशकों की रुचि और परियोजना की व्यावसायिक व्यवहार्यता का आकलन किया जाएगा। इसके बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (त्थ्च्) चरण में अंतिम चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। निगम ने होटल श्रृंखलाओं, रिसॉर्ट डेवलपर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। एपीटीडीसी के अनुसार केवल आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) क्षेत्र का अनुभव रखने वाली कंपनियां ही पात्र होंगी। आवेदकों के लिए 31 मार्च 2025 तक सकारात्मक नेट वर्थ होना अनिवार्य रखा गया है। म्व् जमा करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई, शाम 5 बजे निर्धारित की गई है। अंतिम लीज शर्तें, राजस्व साझेदारी और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान त्थ्च् चरण में तय किए जाएंगे।

संपादकीय

क्या अपराध के आरोप झेल रहे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य होने चाहिए?

दिल्ली आबकारी नीति मामले में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मार्च 2024 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया और जेल से ही दिल्ली सरकार चलाने का निर्णय लिया। कुछ हद तक उन्होंने शासन भी किया। उस समय इस मुद्दे पर देशभर में तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई थी।

हालांकि, दो वर्ष बाद फरवरी 2026 में दिल्ली की अदालत ने इस मामले में केजरीवाल को बरी करते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी। इसी प्रकार, केजरीवाल सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने फरवरी 2026 में मामला खारिज कर दिया। इस दौरान यह बहस प्रमुखता से उठी कि क्या केवल आरोपों के आधार पर किसी जनप्रतिनिधि को पद पर बने रहने से रोका जाना चाहिए, जबकि मुकदमे वर्षों तक लंबित रहते हैं। दूसरी ओर यह तर्क भी दिया गया कि केवल आरोप लग जाने से किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकताय जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए, तब तक उसे निर्दोष माना जाना चाहिए।

ऐसी परिस्थितियों ने देश और राज्यों में सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं की नैतिक जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक का प्रस्ताव रखा है।

इस प्रस्तावित विधेयक के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय या राज्य मंत्री ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार होते हैं जिनकी सजा पांच वर्ष से अधिक है और वे लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं, तो 31वें दिन से उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।

21 अगस्त 2025 को जब यह विधेयक और इससे जुड़े दो अन्य विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए गए, तब भारी हंगामा हुआ। केंद्र सरकार ने इसे राजनीतिक नैतिकता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने वाला कदम करार दिया।

कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने सवाल उठाया कि क्या यह कानून केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी लागू होता, जिन्हें वर्ष 2010 में गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए गिरफ्तार किया गया था। विपक्ष ने तर्क दिया कि यह विधेयक संविधान के उस मूल सिद्धांत के विरुद्ध हो सकता है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है।

इसके बाद संसद ने इन विधेयकों को ध्वनिमत से संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास विचारार्थ भेज दिया। भाजपा सांसद और पूर्व आईएएस अधिकारी अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति को इन विधेयकों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई।

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और वाम दलों ने यह कहते हुए समिति का बहिष्कार किया कि इसमें भाग लेने से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलेगा। वहीं एनसीपी (शरद पवार गुट), एआईएमआईएम, बीजेडी, वाईएसआरसीपी और शिरोमणि अकाली दल जैसे दलों ने समिति की कार्यवाही में भाग लिया।

विधेयक की समीक्षा प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। 17 जुलाई को जेपीसी की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें मसौदा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे पहले एनडीए सदस्य अपने सुझाव समिति को सौंपेंगे। सभी सुझावों को संकलित करने के बाद समिति अपनी सिफारिशों सहित रिपोर्ट संसद को सौंपेगी। जम्मू–कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) पहले ही अपने सुझाव समिति को दे चुके हैं।

यह विधेयक 20 से 27 जुलाई तक प्रस्तावित संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अपराध सिद्ध होने की स्थिति में अयोग्य घोषित करने वाला यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सरकार महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले ''नारी शक्ति वंदन अधिनियम'' सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को भी प्राथमिकता देने की तैयारी में है। इन विधेयकों को पारित कराना एनडीए सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है।

130वें संविधान संशोधन को पारित कराने के लिए संसद में दो–तिहाई विशेष बहुमत आवश्यक होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण से संबंधित राजनीतिक रूप से संवेदनशील 131वां संविधान संशोधन विधेयक भी लाने की तैयारी कर रही है।

आगामी चुनावों से पहले महिलाओं को विधायिकाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून को बिना किसी शर्त लागू करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। इन तीनों कानूनों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार अपने समर्थन आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में विपक्षी दलों के विधायकों और सांसदों का समर्थन जुटाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

इसके साथ ही, जेपीसी की सिफारिशों के आधार पर ''जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक'' तथा ''केंद्र शासित प्रदेश शासन (संशोधन) विधेयक'' भी संसद में पेश किए जाने की संभावना है।

इजरायल–अधिकृत क्षेत्रों पर संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट ने अत्याचारों की निर्ममता को उजागर किया

हर युद्ध अपने पीछे उजड़े हुए शहर, टूटे हुए समाज और शोकाकुल परिवार छोड़ जाता है। लेकिन कुछ युद्ध ऐसी चीज को भी नष्ट कर देते हैं जो दिखाई नहीं देती, फिर भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती हैकृउन संस्थाओं पर विश्वास, जिन्हें मानवता को इतिहास की सबसे भयावह त्रासदियों की पुनरावृत्ति से बचाने के लिए बनाया गया था।

इजरायल और अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग की नवीनतम रिपोर्ट केवल अत्याचारों का एक और विस्तृत दस्तावेज नहीं है। यह इस बात की गंभीर चेतावनी है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था धीरे–धीरे या तो अपनी क्षमता खो रही है, या फिर उन सिद्धांतों को लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति खो रही है, जिन पर उसके अस्तित्व का दावा टिका है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पिछले लगभग आठ दशकों से वैश्विक व्यवस्था एक मूल सिद्धांत पर आधारित रही हैकृकोई भी राष्ट्र, सेना या सशस्त्र समूह अंतरराष्ट्रीय कानून से ऊपर नहीं है। जिनेवा संधियाँ, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय केवल कानूनी मानदंड तय करने के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे कि शक्ति कानून के दायरे में रहे। लेकिन गाजा और अधिकृत वेस्ट बैंक की परिस्थितियाँ संकेत देती हैं कि ये संस्थाएँ अब जवाबदेही सुनिश्चित करने के बजाय केवल साक्ष्य संग्रहण के केंद्र बनकर रह गई हैं।

रिपोर्ट बताती है कि कब्जा और अधिक गहरा हो गया है, बस्तियों का विस्तार अधिक आक्रामक हो गया है और नागरिकों की पीड़ा सामान्य होती जा रही है। आयोग का आरोप है कि इजरायल ने ऐसी परिस्थितियाँ बनाई हैं जिनमें बसने वालों (सेटलर्स) की हिंसा राजनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का साधन बनती जा रही है। साथ ही रिपोर्ट हमास द्वारा फिलिस्तीनियों के खिलाफ की गई फाँसी, यातना और डराने–धमकाने की सुनियोजित कार्रवाइयों को भी उजागर करती है। इस प्रकार आम नागरिक राज्य की शक्ति और उग्रवादी अधिनायकवाद के बीच फँस गए हैं।

अक्सर इस संघर्ष को नैतिकता के दो चरम पक्षों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इजरायल सुरक्षा और 7 अक्टूबर के हमलों की पीड़ा का हवाला देता है, जबकि फिलिस्तीनी दशकों के कब्जे, विस्थापन और भारी सैन्य शक्ति की बात करते हैं। दोनों पक्षों की बातों में कुछ सच्चाई है, लेकिन इनमें से कोई भी नागरिकों पर जानबूझकर हमले, बंधक बनाना, सामूहिक दंड, यातना या जनसांख्यिकीय बदलाव को उचित नहीं ठहरा सकता। अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून राजनीतिक कथाओं को सही साबित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सीमित करने के लिए बनाया गया था।

रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक निष्कर्ष अत्याचारों की सूची से भी आगे जाता है। यह दस्तावेजीकरण और जवाबदेही के बीच बढ़ती खाई को उजागर करता है। संयुक्त राष्ट्र उपग्रह चित्रों, डिजिटल फॉरेंसिक और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के माध्यम से उल्लंघनों का रिकॉर्ड तैयार करने में बेहद सक्षम हो गया है। लेकिन राजनीतिक स्तर पर कार्रवाई लगभग नदारद है। यही आज की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का सबसे बड़ा विरोधाभास है। मानवता के पास अत्याचारों की जानकारी पहले से कहीं अधिक है, फिर भी उन्हें रोकने के प्रयास पहले से कम प्रभावी दिखाई देते हैं। रिपोर्टें तैयार होती हैं, आपात बैठकें बुलाई जाती हैं, प्रस्ताव पारित होते हैं, लेकिन बस्तियों का विस्तार जारी रहता है, रॉकेट दागे जाते हैं, बंधक कैद रहते हैं और आम नागरिक इसकी कीमत चुकाते रहते हैं।

वेस्ट बैंक इसका स्पष्ट उदाहरण है। वर्षों तक बसने वालों की हिंसा को कुछ चरमपंथी तत्वों की अलग–थलग गतिविधि बताया जाता रहा, लेकिन आयोग का कहना है कि हमलों की जांच न होना, अपराधियों पर मुकदमा न चलना और फिलिस्तीनी समुदायों की सुरक्षा न करना एक ऐसी संस्कृति को जन्म दे चुका है, जहाँ दंड से बच निकलना व्यापक राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने लगा है।

रिपोर्ट हमास की भी आलोचना करती है। गाजा में इजरायली सैन्य अभियानों पर दुनिया का ध्यान केंद्रित रहने के बावजूद आयोग ने हमास द्वारा फाँसी, यातना और सार्वजनिक भय के जरिए नियंत्रण स्थापित करने के मामलों को भी दर्ज किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मानवाधिकार किसी राजनीतिक निष्ठा के आधार पर लागू नहीं किए जा सकते। यदि एक पक्ष के अपराधों को नजरअंदाज कर दूसरे पक्ष की निंदा की जाए, तो कानून की सार्वभौमिकता समाप्त हो जाती है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि अंतरराष्ट्रीय कानून की विश्वसनीयता केवल गाजा की घटनाओं से नहीं, बल्कि उस भू–राजनीतिक व्यवस्था से भी प्रभावित हो रही है जिसमें रणनीतिक हित कानून पर हावी हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ वीटो शक्ति अक्सर उन परिस्थितियों में सामूहिक कार्रवाई को रोक देती

है जब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। गाजा संघर्ष ने इन विरोधाभासों को और स्पष्ट कर दिया है। अमेरिका इजरायल की सुरक्षा के समर्थन और मानवीय चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय देश ऐतिहासिक जिम्मेदारियों और घरेलू राजनीतिक दबावों के बीच बँटे हुए हैं। रूस और चीन अंतरराष्ट्रीय कानून के रक्षक होने का दावा करते हैं, जबकि उन पर भी इसी प्रकार के आरोप लगते रहे हैं।वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) के अनेक देशों में यह धारणा मजबूत हुई है कि नियम–आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था सभी पर समान रूप से लागू नहीं होती। चाहे यह धारणा पूरी तरह सही हो या नहीं, इसके गंभीर भू–राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि मानवीय कानून के उल्लंघन की राजनीतिक कीमत लगातार घटती रही, तो भविष्य के युद्ध अधिक क्रूर होंगे। इतिहास बताता है कि कानूनी मानदंड अचानक समाप्त नहीं होते, बल्कि धीरे–धीरे कमजोर पड़ते हैं, जब अपवाद, चयनात्मक कार्रवाई और राजनीतिक समझौते सामान्य बन जाते हैं। आयोग की सबसे गंभीर चेतावनी अगली पीढ़ी को लेकर है। फिलिस्तीनी बच्चे विस्थापन, अभाव और मानसिक आघात के बीच बड़े हो रहे हैं, जबकि इजरायली बच्चे आतंकवाद, असुरक्षा और कठोर राजनीतिक धारणाओं के माहौल में जीवन बिता रहे हैं। हर वर्ष यह संघर्ष अविश्वास को और गहरा कर रहा है तथा हिंसा को सामान्य बना रहा है। इसलिए केवल पुनर्निर्माण, मानवीय सहायता और युद्धविराम से स्थायी शांति संभव नहीं होगी। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जवाबदेही के गहरे संकट का सामना करना होगा। केवल दस्तावेज तैयार करना पर्याप्त नहीं हैय जांचों का परिणाम कानूनी, कूटनीतिक और राजनीतिक कार्रवाई के रूप में सामने आना चाहिए।

अंततः यह रिपोर्ट केवल एक दुखद संघर्ष का विवरण नहीं है, बल्कि इस बात की चेतावनी है कि युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच चुकी है। प्रश्न यह नहीं रह गया है कि उल्लंघन हुए हैं या नहींकृसाक्ष्य पर्याप्त हैं। असली प्रश्न यह है कि क्या दुनिया अब भी मानती है कि अंतरराष्ट्रीय कानून शक्तिशाली और कमजोर, दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यदि इसका उत्तर ''नहीं'' होता है, तो इसके परिणाम गाजा तक सीमित नहीं रहेंगे। भविष्य के युद्धों में वैधता की नहीं, बल्कि राजनीतिक संरक्षण की गणना होगी। और गाजा की सबसे बड़ी त्रासदी केवल उसके नष्ट हुए शहर या बर्बाद जिंदगियाँ नहीं होंगी, बल्कि यह विश्वास का धीरे–धीरे समाप्त होना होगा कि कानून अब भी शक्ति को सीमित कर सकता है। एक बार यदि यह विश्वास समाप्त हो गया, तो उसे फिर से स्थापित करना किसी भी खंडहर बने शहर के पुनर्निर्माण से कहीं अधिक कठिन होगा।

अपने 12 वर्षों के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 102 विदेश यात्राएँ कीं

एक तस्वीर अब अपने आप में एक अलग पहचान बन चुकी हैकृप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फूलों की माला पहने या किसी विदेशी नेता को गले लगाते हुए, एयर इंडिया वन विमान से उतरकर लाल कालीन पर चलते दिखाई देते हैं। यह दृश्य कभी वॉशिंगटन में होता है, कभी अबू धाबी में, कभी टोक्यो में तो कभी रियो डी जेनेरियो में। ऐसी 102 तस्वीरों को जोड़ दें, तो भारत के सबसे अधिक विदेश यात्राएँ करने वाले प्रधानमंत्री का दृश्य इतिहास तैयार हो जाता है।

जून 2026 तक नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक 81 देशों की 102 अंतरराष्ट्रीय यात्राएँ कर चुके हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ चुकी हैं।

अब भारतीय करदाताओं के सामने सवाल यह है कि क्या इन यात्राओं से देश को उतना लाभ मिला है, जितना इन पर खर्च हुआ? या फिर 12 वर्षों की यह शिखर कूटनीति (समिट डिप्लोमेसी) बड़े खर्च पर तैयार की गई एक विदेशी नीति यात्रा–वृत्तांत (ट्रैवलॉग) बनकर रह गई है?

कितना हुआ खर्च?

कई वर्षों तक सरकार ने इन यात्राओं की कुल लागत का एकीकृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया। फरवरी 2026 में विदेश मंत्रालय ने लोकसभा में पूछे गए एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि 2015 से 2025 के बीच प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर सरकारी खजाने से 762 करोड़ रुपये खर्च हुए।

खर्च का रुझान भी दिलचस्प है। वर्ष 2024 में वार्षिक खर्च 100 करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जबकि 2025 में यह बढ़कर 175 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। उस वर्ष प्रधानमंत्री ने यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और पूर्वी एशिया के कई देशों की लंबी यात्राएँ की थीं।

प्रतिनिधिमंडलों का आकार भी बढ़ा है। विभिन्न यात्राओं में 27 से 72 अधिकारियों तक का दल शामिल रहा, जबकि 2025 की एक पांच–देशीय यात्रा में 95 अधिकारी साथ गए थे।

विदेश मंत्रालय का कहना है कि अधिकांश आतिथ्य व्यय मेजबान देश उठाते हैं और भारत केवल सुरक्षा, प्रतिनिधिमंडल तथा मीडिया दल से जुड़े खर्च वहन करता है। यह बात तकनीकी रूप से सही है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि 762 करोड़ रुपये कोई छोटी राशि नहीं है, खासकर ऐसे देश में जहाँ कई राज्य सरकारें मध्याह्न भोजन योजना और सूखा राहत के लिए धन की कमी की बात करती हैं।

क्या कूटनीति का लाभ मिला?

निष्पक्ष मूल्यांकन यह स्वीकार करता है कि कुछ यात्राओं से ठोस परिणाम भी मिले हैं।

– 2022 में हस्ताक्षरित भारत–यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (ब्च्।) ने व्यापार को बढ़ावा दिया और यूएई को भारत के प्रमुख रणनीतिक निवेशकों में शामिल किया।

– अमेरिका के साथ ळम्–भ्।स् जेट इंजन सहयोग, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में साझेदारी और खुफिया सहयोग का विस्तार हुआ।

– क्वाड अब केवल चर्चा मंच नहीं, बल्कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मंच बन चुका है।

– फ्रांस के साथ सहयोग राफेल विमानों से आगे बढ़कर अंतरिक्ष और नागरिक परमाणु ऊर्जा तक पहुंच चुका है।

ये उपलब्धियाँ महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

अधूरे वादों की लंबी सूची

दूसरी ओर कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ अभी भी अधूरी हैं।

– जापान सहयोग से बनने वाली मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना अपने मूल समय–निर्धारण से काफी पीछे चल रही है।

– 2023 जी–20 शिखर सम्मेलन में घोषित भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC), गाजा युद्ध और 2026 के ईरान –अमेरिका संघर्ष जैसी क्षेत्रीय अस्थिरताओं के कारण ठहराव का सामना कर रहा है।

– अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों (MoUs) की प्रगति धीमी रही है।

यही भारतीय कूटनीति की एक संरचनात्मक चुनौती है। किसी डवन्पर हस्ताक्षर करना केवल इरादे की घोषणा होती है, न कि अंतिम अनुबंध। वास्तविक कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषण, पर्यावरणीय मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और निजी निवेश की आवश्यकता होती है, जहाँ अक्सर परियोजनाएँ अटक जाती हैं।

कूटनीति या जनसंपर्क?

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों की विशाल सभाओं और विदेशी नेताओं के साथ सार्वजनिक आत्मीयता को एक नई ऊँचाई दी है।

ह्यूस्टन का ''भ्वूकल डवकप'' कार्यक्रम, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मित्रवत क्षण या विभिन्न नेताओं के साथ उनके चर्चित आलिंगन केवल संयोग नहीं माने जाते। इन्हें एक सुविचारित संचार रणनीति

का हिस्सा माना जाता है, जो विदेश नीति को निरंतर राजनीतिक अभियान के रूप में प्रस्तुत करती है।

समर्थकों का तर्क है कि इससे भारत की वैश्विक छवि मजबूत हुई, प्रवासी भारतीय समुदाय का मनोबल बढ़ा और निवेश आकर्षित करने में मदद मिली। आलोचकों का कहना है कि कई बार प्रतीकात्मकता को वास्तविक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया।

कुछ समस्याएँ जस की तस

प्रधानमंत्री की सक्रिय विदेश नीति के बावजूद कुछ रणनीतिक चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

– चीन के साथ व्यापार लगातार बढ़ रहा है, जबकि दोनों देशों की सेनाएँ सीमा विवाद को लेकर आमने–सामने हैं।

– संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की भारत की मांग आज भी वहीं खड़ी है जहाँ 2014 में थी।

– कई अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं और समझौतों का वास्तविक कार्यान्वयन अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ।

अंतिम निष्कर्ष

इसका अर्थ यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति विफल रही है। यूएई के साथ संबंधों, क्वाड की मजबूती और अमेरिका के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 2014 की तुलना में भारत की वैश्विक स्थिति अधिक मजबूत हुई है।

लेकिन यदि मूल्यांकन यात्राओं की संख्या, देशों की सूची और हस्ताक्षरित समझौतों के आधार पर किया जाए, तो यह भी स्पष्ट है कि उपलब्धियों की तुलना में घोषणाओं और वादों की संख्या अधिक रही है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार कोई ऐसा समेकित सार्वजनिक लेखा–जोखा जारी नहीं करती, जिसमें देशवार और समझौता–वार यह बताया जाए कि क्या वादा किया गया था, क्या पूरा हुआ और क्या अधूरा रह गया।

एक लोकतंत्र में, जहाँ प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर 762 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हों, नागरिक केवल तस्वीरों और प्रेस विज्ञप्तियों से अधिक की अपेक्षा कर सकते हैं। उन्हें एक पारदर्शी रिपोर्ट मिलनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक देश, प्रत्येक समझौते और उसके परिणामों का स्पष्ट विवरण हो।

जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक कूटनीतिक सफलता के दावे और विदेश नीति को केवल दिखावा बताने वाले आरोपकृ दोनों ही पूरी तरह साबित या खारिज नहीं किए जा सकेंगे। यही शायद इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है।

एसआईआर डिजिटलीकरण प्रक्रिया में तेजी लाएं : कलेक्टर

राजमहेंद्रवरम, ३ जुलाई : जिला कलेक्टर कीर्ति चेकूरी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)–2026 के तहत मतदाता सूची डिजिटलीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि जिले में अब तक 38.98 प्रतिशत मतदाता पंजीकरण प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है तथा प्रतिदिन 75,000 से 80,000 रिकॉर्ड अपलोड किए जा रहे हैं। कम प्रगति वाले मतदान केंद्रों की विशेष पहचान कर वहां अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है, ताकि डिजिटलीकरण प्रक्रिया को शत–प्रतिशत पूरा किया जा सके।

मलेरिया नियंत्रण उपायों में तेजी लाने के निर्देश : कलेक्टर

रम्पाचोडावरम, 3 जुलाई : जिला कलेक्टर के. दिनेश कुमार ने जिले में मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिकारियों को नियंत्रण उपायों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। 2 जुलाई को जिले में 15 नए मलेरिया मामले सामने आने के बाद अधिकारियों को व्यापक स्वच्छता अभियान चलाने, सामूहिक जांच (मास स्क्रीनिंग), इंडोर रेजिडुअल स्प्रे (आईआरएस) तथा एंटी–लार्वा अभियान तत्काल शुरू करने के लिए कहा गया है। कलेक्टर ने लोगों से अपने घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देने और बुखार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की है।

दूरदराज के आदिवासी गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी : कलेक्टर

रम्पाचोडावरम, ३ जुलाई : पोलवरम जिला कलेक्टर के. दिनेश कुमार ने आश्वासन दिया कि गुर्तेडु मंडल के बोड्डुगांडी पंचायत के दूरदराज के आदिवासी गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ''एक माह दृ एक विधानसभा क्षेत्र, चार दौरे'' कार्यक्रम के तहत विधायक एवं लेजिस्लेटिव चेयरमैन मिरियाला शिरीषा देवी के साथ आयोजित बैठक में कलेक्टर ने स्थानीय समस्याओं की समीक्षा की और अधिकारियों को सड़क, पेयजल, बिजली, आवास तथा कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए आदिवासियों को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।

ई–फसल पंजीकरण पर झूठे प्रचार पर विश्वास न करें: मंत्री अच्चेन्नायडु

अमरावती, 3 जुलाईः आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री अच्चेन्नायडु ने लोगों से अपील की है कि वे राज्य में ई–फसल पंजीकरण को लेकर विपक्ष के नेता वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी द्वारा किए जा रहे कथित झूठे प्रचार पर विश्वास न करें। उन्होंने आरोप लगाया कि जगन झूठ के राजदूत बन गए हैं और साक्षी असत्य जानकारी फैलाने का मंच बन गया है। मंत्री ने कहा कि किसानों को गुमराह करने की साजिशों को जनता देख रही है और विषैले प्रचार के जरिए सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता।

अच्चेन्नायडु ने बताया कि खरीफ 2025 सीजन में राज्यभर के 53.32 लाख किसानों की 117. 39 लाख एकड़ भूमि का ई–फसल पंजीकरण पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार के कार्यकाल की तुलना में गठबंधन सरकार के दौरान ई–फसल पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि रबी 2025दृ26 सीजन में 99.7 प्रतिशत ई–फसल पंजीकरण पूरा किया गया, जो सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण है। मंत्री ने कहा, "राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए ।च्।प्डै 2.0 के माध्यम से डिजिटल ई–फसल पंजीकरण में तकनीकी क्रांति लाई गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (।प्), जियो–रेफरेंसिंग और उपग्रह तकनीक जैसी आधुनिक प्रणालियों का उपयोग कर पारदर्शी तरीके से ई–फसल पंजीकरण किया जा रहा है। किसानों को सब्सिडी, फसल बीमा और अन्य सरकारी लाभ तेजी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिजिटल क्रॉप सर्वे लागू किया गया है। यह व्यवस्था पूरे देश के लिए एक आदर्श बन रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन सरकार की उपलब्धियों को देखकर जगन असत्य प्रचार कर रहे हैं। नारियल की कीमतों के मुद्दे पर भी साक्षी भ्रामक खबरें प्रकाशित कर रहा है। ऐसी खबरों के जरिए नारियल बाजार को नुकसान पहुंचाने की साजिश की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि झूठे प्रचार के माध्यम से बाजार को प्रभावित करने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

कर्तव्य के साथ मानवताः वार्डन ने कंधे पर उठाकर बच्ची की जान बचाई

पार्वतीपुरम मन्यम जिला, 3 जुलाईः पार्वतीपुरम मन्यम जिले के गुम्मलक्ष्मीपुरम स्थित एक आदिवासी आश्रम विद्यालय की वार्डन हेमा ने एक छात्रा के प्रति असाधारण मानवता का परिचय दिया। तेज बुखार से पीड़ित छात्रा को उन्होंने अपने कंधों पर उठाकर लगभग 6 किलोमीटर तक पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। समय पर इलाज उपलब्ध कराकर उन्होंने छात्रा की जान बचा ली।

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए आंध्र प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष रायापाटी शैलजा ने वार्डन हेमा की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ग पर उनकी सेवा भावना और समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे अधिकारी समाज के लिए प्रेरणा हैं। शैलजा ने ग पर लिखा, "मानवता, सेवा भावना और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल बनीं पार्वतीपुरम मन्यम जिले के गुम्मलक्ष्मीपुरम आदिवासी आश्रम विद्यालय की वार्डन हेमा को हार्दिक बधाई। गंभीर बुखार से पीड़ित छात्रा को अपने कंधों पर उठाकर पहाड़ियों और कठिन रास्तों से लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलकर समय पर चिकित्सा उपलब्ध कराना और उसकी जान बचाना वास्तव में सराहनीय है।आपने यह सिद्ध कर दिया कि कर्तव्य केवल जिम्मेदारी नहीं है,

बल्कि जब उसमें मानवता जुड़ जाती है तो एक जीवन भी बचाया जा सकता है।

विशाखा आर्थिक क्षेत्र के विकास की कुंजी बनेगा बे सिटी प्रोजेक्टः कलेक्टर एम. अभिषिक्त किशोर

विशाखापट्टनम, पेन पह्वर जुलाई ३: प्रस्तावित बे सिटी प्रोजेक्ट विशाखा आर्थिक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस परियोजना के लिए व्यापक एवं दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सके। यह निर्देश जिला कलेक्टर एम. अभिषिक्त किशोर ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए।

बैठक में अधिकारियों ने एरिया डेवलपमेंट प्लान, कैटेलिटिक प्रोजेक्ट्स, स्पैटियल स्टडी, भूमि प्रोफाइलिंग तथा बे सिटी की सीमाओं के निर्धारण सहित विभिन्न विषयों पर पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी। साथ ही परियोजना के तहत विकसित किए जाने वाले बुनियादी ढांचे और भावी विकास योजनाओं की जानकारी भी दी गई।

अधिकारियों के अनुसार, बे सिटी परियोजना 13 गांवों में लगभग 51.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित की जाएगी। परियोजना के अंतर्गत 20.92 किलोमीटर लंबे तटीय कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। इसके अलावा 111.79 किलोमीटर नई ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है, जबकि वर्तमान में इस क्षेत्र में 430.27 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क उपलब्ध है।

समीक्षा बैठक में रणनीतिक सड़कों के निर्माण, विभिन्न क्षेत्रों की क्षमता के आधार पर कैरेक्टर जोन की पहचान, आगामी विकास परियोजनाओं के समन्वय तथा सरकारी भूमि के प्रभावी उपयोग जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

कलेक्टर एम. अभिषिक्त किशोर ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एक समग्र कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि बे सिटी परियोजना को सुनियोजित एवं टिकाऊ शहरी विकास का मॉडल बनाया जा सके।

बैठक में जीवीएमसी आयुक्त केतन गर्ग, वीएमआरडीए आयुक्त तेज भारत, संयुक्त कलेक्टर गोब्बिल्ला विद्याधरी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पोलवरम परियोजना कार्यों का वन अधिकारियों ने किया निरीक्षण

रम्पाचोडावरम, ३ जुलाई : राजमहेंद्रवरम सर्किल की मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) टी. ज्योति और चिंतूर प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) डी. रविंद्रनाथ रेड्डी ने शुक्रवार को इंदिरा सागर पोलवरम परियोजना के अंतर्गत वी.आर. पुरम और कूनवरम वन क्षेत्रों में चल रहे वन विभाग के कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने प्रतिष्ठित सीड बॉल्स कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए बीज चयन, तैयारी और वर्षा ऋतु के दौरान उनके वितरण में गुणवत्ता सुनिश्चित

करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम वनों के पुनरुद्धार, हरित क्षेत्र के विस्तार और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कलेक्टर ने धर्मवरम किसान सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण किया

काकीनाडा, ३ जुलाई : जिला कलेक्टर एम.एन. हरेंधिर प्रसाद ने शुक्रवार को प्रत्तिपाडु मंडल के धर्मवरम किसान सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बीज और उर्वरकों के भंडार की समीक्षा की तथा किसानों से केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने किसानों को बीज वितरित करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरक समय पर उपलब्ध कराए जाएं, वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखी जाए तथा खरीफ सीजन के दौरान किसी प्रकार की कमी न होने दी जाए।

विशाखापत्तनम में पहली बार आयोजित होगी ऐतिहासिक ASMITA साउथ जोन महिला कैनोइंग एवं कयाकिंग लीग

4 और 5 जुलाई को गंभीरामगेड्डा जलाशय में होंगी प्रतियोगिताएं

विशाखापत्तनम, पेन पह्वर, जुलाई ३: भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत आयोजित होने वाली ैडप्ज। साउथ जोन महिला कैनोइंग एवं कयाकिंग लीगदृ2026 का आयोजन पहली बार विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। यह भारत की पहली साउथ जोन ैडप्ज। महिला कैनोइंग एवं कयाकिंग लीग है, जो महिला जल क्रीड़ाओं के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है।

यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 4 एवं 5 जुलाई को विशाखापत्तनम स्थित गंभीरामगेड्डा जलाशय में प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का संयुक्त आयोजन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश (ै।।च) तथा कैनोइंग एवं कयाकिंग एसोसिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश (ब्ज्ञ।।च) द्वारा किया जा रहा है।

प्रतियोगिता के आधिकारिक पोस्टर का अनावरण विशाखापत्तनम के सांसद ने जिला कलेक्टर एवं संयुक्त कलेक्टर की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए पूर्ण सहयोग एवं आवश्यक समन्वय का आश्वासन दिया।

दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाली महिला खिलाड़ी सब–जूनियर, जूनियर, सीनियर एवं महिला वर्ग में कयाक तथा कैनो स्प्रिंट स्पर्धाओं की 200 मीटर, 500 मीटर और 1000 मीटर दौड़ों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी।

इस प्रतियोगिता का उद्देश्य महिलाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना, नई प्रतिभाओं की पहचान करना तथा देशभर में कैनोइंग एवं कयाकिंग खेलों को प्रोत्साहित करना है। साथ ही, गंभीरामगेड्डा जलाशय को एक प्रमुख राष्ट्रीय जल क्रीड़ा केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी यह आयोजन महत्वपूर्ण साबित होगा।

आयोजकों ने खेल प्रेमियों, विद्यार्थियों, परिवारों तथा आम नागरिकों से इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर महिला खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है।

लेडीज़ एंड लेडीज़' के साथ और भी खतरनाक हुई टॉक्सिक की दुनिया

यश लौटेंगे हाई-इम्पैक्ट एक्शन अवतार में

टॉक्सिकः ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स की दुनिया अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक हो गई है। 'लेडीज़ एंड लेडीज़' के लॉन्च के साथ फिल्म का एक नया वीडियो सामने आया है, जो इस डार्क और स्टाइलिश दुनिया की ताकतवर महिलाओं पर रोशनी डालता है। पावर, मिस्ट्री, एटीट्यूड और रोमांच से भरपूर यह वीडियो उन महिला किरदारों की झलक देता है जो इस कहानी को दिशा दे रही हैं — और साफ कर देता है कि वे किसी के बनाए नियमों पर चलने वाली नहीं हैं। नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी हर फ्रेम में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराती हैं। उनके किरदार जितने प्रभावशाली हैं, उतने ही जटिल भी। नयनतारा का तीखा और प्रभावशाली अंदाज़, कियारा की आकर्षक और भावनात्मक झलक, तारा की सहज और जीवंत उपस्थिति, रुक्मिणी की तीव्रता और हुमा की दृढ़ और प्रभावी झलक — हर एक किरदार टॉक्सिक की दुनिया पर अपनी अलग छाप छोड़ता है। इस पूरे माहौल को और गहराई देता है एक प्रभावशाली महिला वॉइस-ओवर, जो कहानी को एक महिला के दृष्टिकोण से पेश करता है और उसमें रहस्य, शक्ति और विद्रोह की भावना जोड़ता है। वीडियो की शुरुआत से ही इसका विद्रोही अंदाज़ साफ नजर आता है, जब स्क्रीन पर एक चेतावनी दिखाई देती हैः "बच्चे दूर रहें। माता-पिता अपने बच्चों को दूर रखें। दादा-दादी अपने बच्चों के बच्चों को भी दूर रखें। परदादा-परदादी अपनी जिम्मेदारी पर देखें।" यह बेबाक और साफ चेतावनी फिल्म के मूड को पूरी तरह दर्शाती है। टॉक्सिकः ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स का यह नया प्रस्तुतीकरण एक ऐसी दुनिया को और विस्तार देता है, जो जितनी खतरनाक है उतनी ही आकर्षक भी। प्रभावशाली विजुअल्स, स्टाइलिश एक्शन और रहस्य से भरे माहौल के साथ यह फिल्म एक अलग तरह का सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है।

गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी और अभिनेता-निर्माता यश के नेतृत्व में तैयार टॉक्सिकः ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स में नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। यह फिल्म कन्नड़ और अंग्रेज़ी में एक साथ शूट की गई है और हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में भी डब की जाएगी। केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले बनी यह फिल्म 26 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

काजोल का मजेदार अंदाज, बोलीं–'जो मेरी पोस्ट पसंद करते हैं, वही सबसे ज्यादा खुश, समझदार और खूबसूरत हैं'

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री काजोल अपनी शानदार अदाकारी के साथ-साथ अपने चुलबुले अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। वह जब भी सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करती हैं तो उनके फैंस उसे खूब पसंद करते हैं। इस बार भी उन्होंने अपनी एक नई फोटो पोस्ट की, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा उनके साथ लिखे गए मजेदार कैप्शन की हो रही है।

काजोल ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक मुस्कुराती हुई सेल्फी पोस्ट की। यह सेल्फी उन्होंने कार के अंदर क्लिक की है। लुक की बात करें तो वह पिंक कलर की साड़ी में नजर आ रही है। इसके साथ उन्होंने डायमंड और रूबी चोकर नेकलेस पहना हुआ है। लाइट मेकअप के साथ उनका लुक काफी आकर्षक लग रहा है। तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, मेरी बनाई हुई एक स्टडी के अनुसार, जो लोग मेरे पोस्ट लाइक करते हैं, वे उन लोगों की तुलना में ज्यादा खुश, ज्यादा इंटेलिजेंट और बेहतर दिखने वाले होते हैं, जो उन्हें लाइक नहीं करते।

अगर काजोल के अभिनय सफर की बात करें तो उन्होंने साल 1992 में 'बेखुदी' फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्मों जैसे- 'बाजीगर', 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'करण अर्जुन', 'गुप्त', 'प्यार तो होना ही था', 'कुछ कुछ होता है', 'कभी खुशी कभी गम', 'फना', 'माय नेम इज खान', 'दिलवाले', 'तान्हाजीः द अनसंग वॉरियर' और 'लस्ट स्टोरीज 2' में काम किया। फैंस उनकी जोड़ी को अभिनेता शाहरुख खान के साथ ज्यादा पसंद करते है। वह मशहूर अभिनेत्री तनुजा और दिवंगत फिल्म निर्माता शोमू मुखर्जी की बेटी हैं। उन्होंने साल 1999 में अभिनेता अजय देवगन से शादी किया। दोनों के दो बच्चे हैं, बेटी न्यासा देवगन और बेटा युग देवगन।

फरीदा जलाल और किरण कुमार का 'वेलकम टू द जंगल की सफलता में आशीर्वाद शामिल : अक्षय कुमार

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म को रिलीज के बाद से ही दर्शकों और समीक्षकों दोनों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इसी बीच अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया, जिसमें फिल्म से जुड़े वरिष्ठ कलाकारों फरीदा जलाल और किरण कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया। अक्षय ने कहा कि फिल्म की सफलता में उनका आशीर्वाद और अनुभव शामिल है। अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह फरीदा जलाल और किरण कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में तीनों मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने पोज देते दिखाई दे रहे हैं। इसी तस्वीर के साथ अक्षय ने कैप्शन में अपने दिल की बात साझा की है। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, अगर एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है, तो यह तस्वीर मेरे लिए लाखों इमोशन्स के बराबर है। 'बड़ी बी' सही कह रही हैं। इस समय जो मैं महसूस कर रहा हूं, उसके सामने धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है।

उन्होंने आगे कहा, मैं 'वेलकम टू द जंगल' से जुड़े हर एक व्यक्ति का आभारी हूं, लेकिन खास तौर पर मैं फरीदा जी और किरण सर जैसे दिग्गज कलाकारों के सामने नतमस्तक हूं। शायद इन्हीं के आशीर्वाद से हमारी फिल्म को दर्शकों का इतना अपार प्यार मिल रहा है। पूरी टीम की तरफ से आप सभी को प्यार। जय महाकाल।

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' लोकप्रिय 'वेलकम' फिल्म फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है। इस फिल्म का निर्देशन अहमद खान ने किया है, जबकि इसका निर्माण फिरोज ए. नाडियाडवाला ने किया है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, संजय दत्त, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, दलेर मेहंदी, फरीदा जलाल और किरण कुमार जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। यह फिल्म 22 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और रिलीज के बाद से ही इसे दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

सनी देओल के साथ काम करना मेरे करियर के लिए सौभाग्य की बात : दीया मिर्जा

अभिनेत्री दीया मिर्जा ने अभिनेता सनी देओल के साथ काम करने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभिनेता के साथ काम करना, उनके करियर के लिए सौभाग्य की बात है। फिल्म 'इक्का' में दीया मिर्जा और सनी देओल साथ दिखाई देंगे। 'इक्का' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में बात करते हुए दीया ने कहा कि वह हमेशा से देओल परिवार की प्रशंसक रही हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए हां कहने की वजह बताते हुए दीया ने कहा, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे यह बहुत दिलचस्प, मानवीय और दमदार लगी। इसमें किरदारों को बहुत अनोखे, दिलचस्प और आकर्षक ढंग से दिखाया गया है, इसलिए मुझे हां कहना ही पड़ा। सनी देओल के साथ काम करना मेरे करियर के लिए सौभाग्य की बात है और मैं इसे लेकर बहुत खुश थी।

उन्होंने अपने को-स्टार्स तिलोत्तमा शोम और अक्षय खन्ना की भी तारीफ की। दीया मिर्जा ने कहा कि मैं हमेशा से देओल परिवार की दयालुता, उदारता और जमीन से जुड़े रहने की तारीफ करती रही हूं। सनी देओल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा मैंने सोचा था, बल्कि उससे भी बेहतर। मैंने टीजर लॉन्च के समय भी यह बात कही थी। ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना जिसमें तिलोत्तमा शोम और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार हों, यह सच में अद्भुत है और सिद्धार्थ ने कहानी को बहुत संवेदनशीलता और समझदारी से पेश किया है।

दीया मिर्जा ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहा कि अवंतिका एक ऐसी महिला है जो अपने आसपास के लोगों को अपनापन, हिम्मत और स्थिरता देती है, तब भी जब जिंदगी बहुत अनिश्चित हो जाती है। मैं उसकी हिम्मत और उस शांत साहस से प्रभावित हुई जिसके साथ वह अपनी चुनौतियों का सामना करती है।

उन्होंने कहा कि 'इक्का' की खासियत यह है कि कोर्टरूम ड्रामा के पीछे परिवार, प्यार और मुश्किल फैसलों की एक गहरी मानवीय कहानी है। मैं नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी कहानी के साथ वापसी करके बहुत खुश हूं जो भावनात्मक रूप से समृद्ध और बहुत दिलचस्प है, और मुझे उम्मीद है कि दर्शक इसे जरूर देखेंगे।

'मैं वापस आऊंगा' मूवी ने कृति खरबंदा को घर की याद दिलाई

अभिनेत्री कृति खरबंदा ने इम्तियाज़ अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक नोट साझा किया है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म ने उन्हें भीतर तक छू लिया और उनके दिवंगत दादाजी और नानाजी की यादें ताज़ा कर दी हैं। फिल्म से जुड़ी अपनी भावनाएं साझा करते हुए कृति ने लिखा है कि इस फिल्म को उन्हें अपने ₹दादू₹ और ₹नानू₹ दोनों की याद आ गई। उन्होंने कहा कि वह उन्हें हर दिन याद करती हैं, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें रुककर उनके सभी त्यागों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जो पिछली पीढ़ियों ने किए थे। उन्होंने लिखा कि हम अक्सर जिस ज़मीन पर खड़े होते हैं, उसे सामान्य मान लेते हैं, बिना यह समझे कि शायद किसी ने वहां तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी दुनिया पीछे छोड़ दी होगी।

लिखा है, ₹शायद घर सिर्फ वह जगह नहीं होती जहां हम रहते हैं। कभी-कभी घर वह भी होता है, जहां हम कभी वापस नहीं जा पाते।₹ उनके अनुसार, घर केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना भी हो सकता है, जो हमेशा हमारी यादों में जीवित रहती है, भले ही वहां लौट पाना संभव न हो।

कृति ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि इसका प्रभाव इसकी अवधि से कहीं अधिक बड़ा है। उन्होंने लिखा कि कुछ कहानियां पर्दा गिरने के साथ खत्म नहीं होतीं, बल्कि दर्शकों के साथ उनके घर तक जाती हैं और लंबे समय तक उनके दिलों में बस जाती हैं।

अपने भावुक संदेश के अंत में कृति ने फिल्म की पूरी टीम का धन्यवाद भी किया है कि उन्होंने एक आम इंसान को नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपना आभार अपने दादू, नानू और उन जैसे अनगिनत लोगों को समर्पित करते हुए लिखा है, शुक्रिया मेरे दादू और नानू जैसे उन सभी आम आदमी को हीरो बनाने के लिए।₹ इसी के साथ उन्होंने अपने इस संदेश का समापन दिल वाले इमोजी के साथ किया है।

कृति खरबंदा का यह भावनात्मक संदेश सोशल मीडिया पर प्रशंसकों के दिलों को छू रहा है और यह दिखाता है कि 'मैं वापस आऊंगा' ने दर्शकों पर कितना गहरा भावनात्मक प्रभाव छोड़ा है।

मुंबई की लोकल ट्रेन में गुजरे मेरे संघर्ष के दिन : रिद्धि डोगरा

रिद्धि डोगरा उन अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिन्हें सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में काम किया। अच्छी एक्टिंग की वजह से उन्हें शाहरुख खान जैसे बिग स्टार के साथ काम करने का मौका मिला। अभिनेत्री की खास बात यह है कि वह आज सफल हैं। लेकिन, उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद रखा है। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए भीड़-भाड़ वाली लोकल ट्रेनों में सफर करने के दिनों को याद किया। उन्होंने उन मुश्किलों का जिक्र किया, जिनका उन्होंने सामना किया और उस दृढ़ संकल्प के बारे में बताया, जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनके रास्ते को आकार दिया। रिद्धि ने लिखा कि मुझे हमेशा से जुलाई का महीना पसंद रहा है। इन तस्वीरों ने जुलाई के पुराने दिनों की यादें ताजा कर दीं। जुलाई 2005 में मेरी मुंबई की कहानी शुरू हुई थी। कॉलेज से नई-नई निकली थी और बड़ी दुनिया में पढ़ने, घूमने-फिरने, जीने और सीखने के लिए उत्सुक थी। इसीलिए, मैंने मुंबई को चुना। यह एक ऐसा शहर है, जो अनजाने में मुझे लंबे समय से बुला रहा था। मुझे इस शहर की हलचल भरी जिंदगी और आकर्षण में सुकून मिलता है।

रिद्धि डोगरा ने लिखा कि लोकल ट्रेनें मेरी सबसे पसंदीदा जगह बन गई थीं। 2005 से 2007 के बीच मैं एक ही दिन में कई तरह के वाहनों से सफर करती थी। पहले कॉलेज जाती, फिर अपनी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की नौकरी पर जाती। मैं पूरा समय ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए और अपने भविष्य के सपनों के बारे में सोचते हुए मुस्कुराती रहती थी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा भविष्य बहुत शानदार होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं अपनी किस्मत की खुद मालिक थी। आज जिसे हम विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन कहते हैं, वह मैं उन दिनों रोज करती थी। लोग उसे 'दिन में सपना देखना' कहते थे। इस दौरान एक गाना मेरे आईपॉड पर सबसे ज्यादा चलता था।

रिद्धि डोगरा को असुर में नुसरत, ऑल्ट बालाजी की द मैरिड वुमन में आस्था, स्टार प्लस की मर्यादाः लेकिन कब तक? में प्रिया और वो अपना सा में निशा का किरदार निभाने के लिए पहचान मिली। वह नच बलिए 6 और फियर फैक्टरः खतरों के खिलाड़ी 6 जैसे लोकप्रिय रियलिटी शो में भी नजर आ चुकी हैं। रिद्धि डोगरा द साबरमती रिपोर्ट, लकड़बग्घा, और जवान जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं।

एस.एस. राजामौली ने महेश बाबू की तारीफ की

कहा- वो फोन कार में रखकर सिर्फ सेट पर फोकस करते हैं

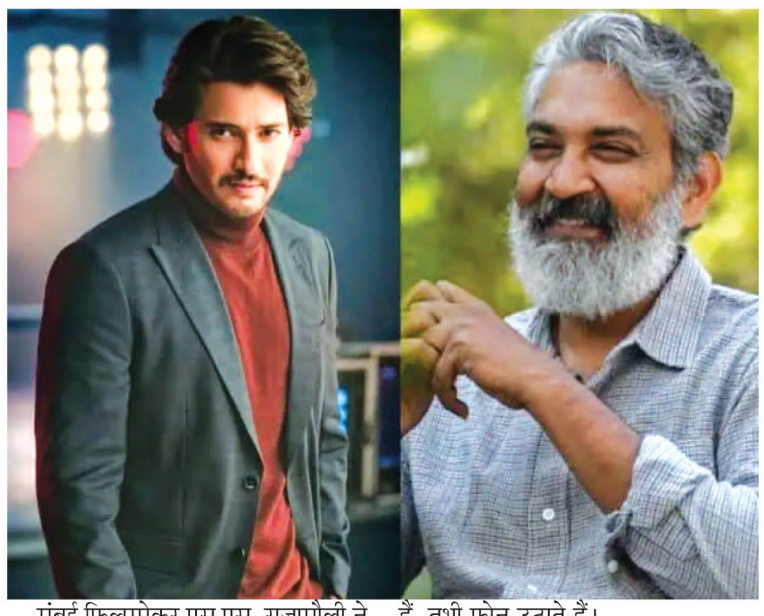

मुंबई फिल्ममेकर एस.एस. राजामौली ने हाल ही में एक इंटरव्यू में महेश बाबू के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' पर काम करने का अनुभव साझा किया और बताया कि आखिर क्या चीज उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई। जहां एक तरफ वह सालों से महेश के अभिनय के फैन रहे हैं, वहीं इस बार उन्हें जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वो थी महेश बाबू का जबरदस्त अनुशासन, प्रोफेशनल रवैया और सेट पर उनका अटूट फोकस।

राजामौली ने कहा, एक अभिनेता के तौर पर मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं उनके काम को लंबे समय से देख रहा हूं। मुझे पता है वो क्या कर सकते हैं। लेकिन जिसने मुझे सच में सरप्राइज किया, वो है उनका काम करने का तरीका। उन्होंने महेश बाबू की एक खास आदत का जिक्र किया जो उन्हें बेहद अलग लगी। उनके मुताबिक, महेश शूट के दौरान अपना फोन पूरी तरह दूर रखते हैं, जिससे उनका पूरा ध्यान सिर्फ काम पर रहता है। वो ऑफिस में बिना फोन के आते हैं। फोन कार में ही छोड़ देते हैं और सीधे अंदर आते हैं। शूट के दौरान मैंने उन्हें कभी सेट पर फोन के साथ नहीं देखा। जब वो वापस कार में जाते हैं, तभी फोन उठाते हैं।

राजामौली ने आगे बताया कि महेश का यह अनुशासन सिर्फ फोन से दूर रहने तक सीमित नहीं है। ब्रेक के समय भी वो फोन में उलझने के बजाय चुपचाप आसपास हो रही हर चीज को ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं। कभी कभी दो तीन घंटे तक वो बस अपनी जगह बैठकर लोगों को काम करते हुए देखते रहते हैं। ना फोन, ना कोई डिस्टर्बेंस, सिर्फ ऑब्जर्वेशन।

राजामौली ने यह भी माना कि महेश बाबू की इस आदत ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भी प्रेरित किया है। अब वो भी परिवार के साथ समय बिताते वक्त फोन से दूर रहने की कोशिश करते हैं। जहां महेश बाबू को हमेशा से उनकी ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस के लिए सराहा गया है, वहीं राजामौली की ये बात उनके ऑफ स्क्रीन अनुशासन और फोकस की एक नई झलक देती है, जो उन्हें इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित सितारों में शामिल करती है। दर्शक अब उन्हें राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' में देखेंगे, जिसमें प्रियंका चोपड़ा जोनस और पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आएंगे। यह फिल्म 7 अप्रैल 2027 को दुनियाभर में रिलीज होने वाली है।

विशेष रूप से निर्देशक इम्तियाज़ अली को संबोधित करते हुए कृति ने लिखा है, ₹आपकी फिल्में अक्सर घर जैसी लगती हैं। इस बार घर नहीं मिला... इस बार घर की याद मिल गई।₹ उनके इन शब्दों ने खूबसूरती से यह एहसास बयां किया कि फिल्म ने सिर्फ 'घर' की कहानी नहीं दिखाई, बल्कि घर की गहरी याद और उससे जुड़ी भावनाओं को जगा दिया है।

कृति ने आगे लिखा कि 'मैं वापस आऊंगा' देखने के बाद ₹घर₹ का अर्थ उनके लिए पूरी तरह बदल गया है। उन्होंने

Printed and Published by **GANTYADA APPARAO** on behalf of **GANTYADA APPARAO**, Printed at Sri Sai Ganga Printers and Publishers Flat No: 504, Bharat Towers, 5th Lane, Dwaraka Nagar, Visakhaptanam, Andhra Pradesh-530016, and Published at H.NO: 38-4-216, MAHARANI STREET, MARRIPALEM, Visakhapatnam, Andhra Pradesh-530018, **Editor: GANTYADA APPARAO.** Mobile : 9059465965, **RNI : APHIN/26/A3657**, editorpenpower@gmail.com